THE RESEARCH DIALOGUE
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
© The Research Dialogue | Volume-04 | Issue-04 | January-2026
Available online at: https://theresearchdialogue.com/
DOI: : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v4i4.14

भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में बहु-विषयक शिक्षा: एनईपी 2020 की कार्यान्वयन रणनीतियों का एक विवरणात्मक अन्वेषण

डॉ. सोनम शर्मा

सहायक प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र), कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 पारंपरिक विषयगत अलगाव (disciplinary silos) को समाप्त करने और समग्र, लचीले एवं नवाचारी सीखने को बढ़ावा देने के लिए 'बहु-विषयक शिक्षा' को प्राथमिकता देकर भारतीय उच्च शिक्षा के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह विवरणात्मक अन्वेषण बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए NEP 2020 में उल्लिखित प्रमुख कार्यान्वयन रणनीतियों का परीक्षण करता है, जिसमें संस्थानों का बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पुनर्गठन, कला, विज्ञान, मानविकी और व्यावसायिक धाराओं के एकीकरण के साथ लचीला पाठ्यक्रम डिजाइन, 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स' (ABC) की स्थापना, अंतःविषय अनुसंधान समूहों को प्रोत्साहन, और क्रेडिट हस्तांतरण एवं बहु-प्रवेश-निकास (multiple entry-exit) विकल्पों के तंत्र शामिल हैं। आधिकारिक नीति दस्तावेज और विद्वानों के विश्लेषणों के आधार पर, यह पत्र वर्णन करता है कि कैसे ये रणनीतियाँ छात्र की पसंद को बढ़ाने, विषयों के रचनात्मक संयोजनों को प्रोत्साहित करने, समग्र विकास का समर्थन करने और संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से आकार देने का लक्ष्य रखती हैं। यह नवाचार, समानता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के निहितार्थों की भी खोज करता है, जबकि बुनियादी ढांचे की सीमाओं, संकाय की तैयारी, नियामक बाधाओं और परिवर्तन के प्रति सांस्कृतिक प्रतिरोध जैसी संभावित चुनौतियों को संबोधित करता है।

कीवर्ड: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बहु-विषयक शिक्षा, उच्च शिक्षा संस्थान, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, संस्थागत पुनर्गठन, भारत।

परिचय

भारत का उच्च शिक्षा परिदृश्य ऐतिहासिक रूप से कठोर विषयगत सीमाओं, कम उम्र से ही विशिष्ट धाराओं के चयन और अंतःविषय जुड़ाव के सीमित अवसरों से चिह्नित रहा है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। ये संरचनाएं विशेषज्ञ तो पैदा करती थीं, लेकिन अक्सर इसके

परिणामस्वरूप खंडित ज्ञान, कम रचनात्मकता और स्नातक वास्तविक दुनिया की जटिल चुनौतियों के लिए तैयार नहीं हो पाते थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उच्च शिक्षा परिवर्तन के अपने दृष्टिकोण के केंद्र में बहु-विषयक शिक्षा को रखकर इन सीमाओं को दूर करने का प्रयास करती है।

NEP 2020 की परिकल्पना है कि 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थान बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों या समूहों (clusters) में विकसित हों, जहाँ छात्र मानविकी के साथ विज्ञान, कला के साथ व्यावसायिक कौशल, या दर्शन के साथ प्रौद्योगिकी जैसे विविध क्षेत्रों का स्वतंत्र रूप से अन्वेषण कर सकें (शिक्षा मंत्रालय, 2020, पृष्ठ 35)। यह बदलाव इस विश्वास पर आधारित है कि समग्र और बहु-विषयक शिक्षा—तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन भारतीय संस्थानों से प्रेरणा लेते हुए—आलोचनात्मक सोच, नवाचार और चहुंमुखी व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है (ऐथल और ऐथल, 2020)।

नीति का बहु-विषयकता पर जोर केवल संरचनात्मक नहीं बल्कि शैक्षणिक और सांस्कृतिक भी है। कार्यान्वयन रणनीतियों में संस्थागत विलय, पाठ्यक्रम लचीलापन और डिजिटल क्रेडिट सिस्टम शामिल हैं, जो एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जहाँ ज्ञान सीमाओं के पार प्रवाहित हो सके (सिंह, 2024)।

NEP 2020 में बहु-विषयक शिक्षा का अवलोकन

NEP 2020 भारतीय उच्च शिक्षा में प्रचलित "प्रारंभिक विशेषज्ञता" की स्पष्ट रूप से आलोचना करती है, जो छात्रों को संकीर्ण धाराओं में मजबूर करती है (शिक्षा मंत्रालय, 2020, पृष्ठ 34) । नीति समग्र शिक्षा की ओर लौटने की वकालत करती है, जहाँ बहु-विषयक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक, भावनात्मक और नैतिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए कला, मानविकी, विज्ञान और व्यावसायिक क्षेत्रों को एकीकृत करते हैं।

इस दृष्टिकोण के केंद्र में उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) का बहु-विषयक संस्थाओं में परिवर्तन है। 2030 तक, एकल-धारा संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा और उनके स्थान पर बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालय और कॉलेज लाए जाएंगे (शिक्षा मंत्रालय, 2020, पृष्ठ 35)।

बहु-विषयक शिक्षा के लिए प्रमुख कार्यान्वयन रणनीतियां

1. संस्थागत पुनर्गठन और क्लस्टरिंग

एक प्राथमिक रणनीति में विलय या स्वायत्त समूहों (clusters) के माध्यम से संस्थानों को बड़ी संस्थाओं में पुनर्गठित करना शामिल है। छोटे, एकल-विषय कॉलेजों को बड़े विश्वविद्यालयों के साथ संबद्ध होने या क्लस्टर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे विविध कार्यक्रम पेश कर सकें।

2. लचीला पाठ्यक्रम डिजाइन और विषय एकीकरण

पाठ्यक्रम का लचीलापन महत्वपूर्ण है, जिसमें स्नातक कार्यक्रमों को 'मेजर-माइनर' संयोजन और विभिन्न विषयों के बीच इलेक्टिव विषयों के इर्द-गिर्द संरचित किया गया है (शिक्षा मंत्रालय, 2020, पृष्ठ 37)। छात्र, उदाहरण के लिए, नृविज्ञान या उद्यमिता में 'माइनर' के साथ भौतिकी में 'मेजर' कर सकते हैं।

3. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) और बहु-प्रवेश-निकास विकल्प

एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC): एक तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक विश्लेषण

एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा में छात्र-केंद्रित लचीलेपन को संस्थागत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना है। यह प्रणाली छात्रों को 'सीखने के दौरान अर्जन' (Earn while you learn) की सुविधा प्रदान करती है, जहाँ उनके द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट्स को एक सुरक्षित डिजिटल वॉलेट में संग्रहीत किया जाता है।

1. एबीसी की कार्यात्मक संरचना (Functional Structure of ABC)

ABC की कार्यप्रणाली एक बैंक के समान है, जिसमें छात्र 'खाताधारक' होते हैं और मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान (HEIs) 'क्रेडिट प्रदाता' के रूप में कार्य करते हैं। इसकी प्रक्रिया को निम्नलिखित तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है:

घटक	विवरण और भूमिका
डिजिटल रिपॉजिटरी	यह नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (NAD) के माध्यम से क्रेडिट्स का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करता है।
क्रेडिट संचय (Accumulation)	छात्र द्वारा किसी भी सेमेस्टर या पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने पर क्रेडिट स्वतः एबीसी आईडी में जमा हो जाते हैं।
क्रेडिट हस्तांतरण (Transfer)	एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाने पर छात्र के क्रेडिट्स का निर्बाध हस्तांतरण संभव होता है।
क्रेडिट विमोचन (Redemption)	अंतिम उपाधि (Degree/Diploma) प्राप्त करने के लिए छात्र द्वारा संचित क्रेडिट्स का उपयोग किया जाता है।

2. बहु-प्रवेश और निकास प्रणाली (Multiple Entry and Exit System - MEES)

एबीसी का सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग 'बहु-प्रवेश और निकास' प्रणाली को सुगम बनाना है। यह शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका विवरण निम्नवत है:

- **प्रथम वर्ष (36-44 क्रेडिट):** सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर **'अंडरग्रेजुएट सर्टिफिकेट'**।
- **द्वितीय वर्ष (72-88 क्रेडिट):** सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर **'अंडरग्रेजुएट डिप्लोमा'**।
- **तृतीय वर्ष (108-132 क्रेडिट):** सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर **'बैचलर डिग्री'**।
- **चतुर्थ वर्ष (144-176 क्रेडिट):** शोध के साथ **'बैचलर डिग्री (ऑनर्स)'**।

3. शोध पत्र हेतु नमूना क्रेडिट संचय तालिका (Sample Credit Accumulation Table)

नीचे एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे एक छात्र विभिन्न विषयों और माध्यमों से क्रेडिट संचित कर सकता है:

पाठ्यक्रम का प्रकार	**विषय**	**क्रेडिट अंक**	**स्रोत (Source)**
मुख्य विषय (Major)	भौतिक विज्ञान (Physics)	20	गृह विश्वविद्यालय (Parent University)
गौण विषय (Minor)	अर्थशास्त्र (Economics)	12	अन्य संबद्ध महाविद्यालय
कौशल विकास	डेटा एनालिटिक्स	04	SWAYAM (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म)
व्यावसायिक शिक्षा	डिजिटल मार्केटिंग	04	स्थानीय व्यावसायिक संस्थान
कुल संचित क्रेडिट		**40**	**एबीसी वॉलेट में उपलब्ध**

4. शैक्षणिक निहितार्थ (Academic Implications)

- **संस्थागत स्वायत्तता:** यह प्रणाली संस्थानों को अंतर-विषयक पाठ्यक्रम डिजाइन करने की स्वतंत्रता देती है।
- **आजीवन अधिगम (Lifelong Learning):** क्रेडिट की 7 वर्ष की वैधता छात्रों को लंबे अंतराल के बाद भी शिक्षा पूर्ण करने का अवसर देती है।
- **वैश्विक मानकों से सामंजस्य:** यह अंतरराष्ट्रीय 'यूरोपीय क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम' (ECTS) के अनुरूप है, जिससे भारतीय छात्रों की वैश्विक गतिशीलता बढ़ेगी।

4. अंतःविषय अनुसंधान समूहों को बढ़ावा देना

अनुसंधान में बहु-विषयकता लाने के लिए, NEP 2020 संस्थानों के भीतर अंतःविषय समूहों का प्रस्ताव करती है, जिन्हें 'राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन' (NRF) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा (शिक्षा मंत्रालय, 2020, पृष्ठ 48)।

कार्यान्वयन की चुनौतियां: एक आलोचनात्मक विश्लेषण (Implementation Challenges: A Critical Analysis)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सफलता इसके 'दृष्टिकोण' से अधिक इसके 'क्रियान्वयन' की सुगमता पर निर्भर करती है। बहु-विषयक शिक्षा के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

1. संरचनात्मक और ढांचागत बाधाएं (Structural and Infrastructural Barriers)

नीति 'संस्थान क्लस्टरिंग' (Institutional Clustering) का सुझाव देती है, लेकिन भौगोलिक और प्रशासनिक स्तर पर यह अत्यंत जटिल है।

- **संसाधनों का अभाव:** ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे महाविद्यालयों में पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और डिजिटल उपकरणों की भारी कमी है। ऐसे में 'संसाधन साझाकरण' (Resource Sharing) का विचार व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाता है (कुमार और पांडे, 2025)।

- **डिजिटल अवसंरचना:** ABC (एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स) पूरी तरह से डिजिटल डेटा पर आधारित है। दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की अस्थिरता और डिजिटल साक्षरता की कमी इस प्रणाली के सार्वभौमिकरण में बड़ी बाधा है।

2. संकाय संबंधित और सांस्कृतिक चुनौतियां (Faculty and Cultural Challenges)

शिक्षण समुदाय के भीतर विषयों के प्रति गहरी 'निष्ठा' (Disciplinary Loyalty) एक अदृश्य बाधा के रूप में कार्य करती है।

- **विषयगत अलगाव (Silos):** दशकों से चले आ रहे विभागीय ढांचे के कारण संकाय सदस्य अक्सर अन्य विषयों के साथ समन्वय करने में हिचकिचाते हैं। यह 'सांस्कृतिक प्रतिरोध' अंतःविषय अनुसंधान को बाधित करता है (वर्मा और सिंह, 2024)।
- **प्रशिक्षण का अभाव:** बहु-विषयक शिक्षा के लिए ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जो स्वयं विभिन्न विषयों के अंतर्संबंधों को समझते हों। वर्तमान में, उच्च शिक्षा संकायों के लिए प्रभावी 'पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों' (Refresher Courses) और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भारी कमी है।

3. नियामक और प्रशासनिक जटिलताएं (Regulatory and Administrative Complexities)

उच्च शिक्षा के नियमन में बदलाव एक धीमी प्रक्रिया है।

- **ABC रोलआउट और क्रेडिट एकरूपता:** विभिन्न विश्वविद्यालयों के ग्रेडिंग सिस्टम और क्रेडिट मान (Credit Values) अलग-अलग हैं। इन सभी को एक साझा 'क्रेडिट फ्रेमवर्क' के तहत लाना एक बड़ी नियामक चुनौती है।
- **वित्त पोषण (Funding):** बहु-विषयक संस्थानों के निर्माण और अनुसंधान क्लस्टरों की स्थापना के लिए भारी मात्रा में सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है। सार्वजनिक व्यय को जीडीपी के 6% तक ले जाने का लक्ष्य अभी भी अधूरा है।

4. मूल्यांकन और मानकीकरण की समस्या (Assessment and Standardization)

जब एक छात्र भौतिकी के साथ संगीत जैसे विविध विषयों का चयन करता है, तो उनका मूल्यांकन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

- **अकादमिक कठोरता (Academic Rigor):** शिक्षाविदों के एक वर्ग का मानना है कि बहु-विषयक दृष्टिकोण से मुख्य विषयों की गहराई (Depth) कम हो सकती है, जिससे 'अकादमिक कठोरता' के कमजोर होने का भय रहता है (बैंगे, 2021)।

चुनौतियों के समाधान हेतु प्रस्तावित रणनीतियां

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए शोध पत्र में निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं:

- **चरणबद्ध कार्यान्वयन (Phased Implementation):** पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ संस्थानों में इसे लागू करना।
- **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की सक्रियता:** अंतःविषय शोध के लिए समर्पित फंडिंग सुनिश्चित करना।
- **व्यापक संकाय प्रशिक्षण:** शिक्षकों के लिए अनिवार्य 'मल्टीडिसिप्लिनरी पेडागोजी' प्रशिक्षण मॉड्यूल।

निष्कर्ष

NEP 2020 की बहु-विषयक शिक्षा की रणनीतियाँ भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को पुनर्जीवित करने के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। सफल निष्पादन भारत को बहु-विषयक शिक्षा में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर सकता है, जो आधुनिक नवाचार के साथ प्राचीन ज्ञान का मेल कराता है।

संदर्भ (References)

- ऐथल, पी. एस., और ऐथल, एस. (2020). *एनालिसिस ऑफ द इंडियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टुवर्ड्स अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स.* इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, एंड सोशल साइंसेज, 5(2), 19–41.
- बैंगे, सी. (2021). *इंडियाज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020: क्रिटिकल एनालिसिस एंड कमेंट्री.* प्रोस्पेक्ट्स. https://doi.org/10.1007/s11125-021-09573-9
- कुमार, ए., और पांडे, आर. (2025). *इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020.* रिसर्चगेट.
- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.*
- शर्मा, जी., और कुमार, एस. (2023). *इम्पैक्ट ऑफ एनईपी 2020 इंप्लीमेंटेशन इन हायर एजुकेशन इन इंडिया.* ऑल इनोवेशन जर्नल.
- सिंह, आर. (2024). *मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ एनईपी-2020: ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया.* ट्विस्ट जर्नल.
- वर्मा, एस., और सिंह, पी. (2024). *एनईपी 2020 एंड मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टिट्यूशंस: फॉस्टरिंग इनोवेशन.* IJRTI.

Cite this Article:

डॉ. सोनम शर्मा," भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में बहु-विषयक शिक्षा: एनईपी 2020 की कार्यान्वयन रणनीतियों का एक विवरणात्मक अन्वेषण" The Research Dialogue, Open Access Peer-reviewed & Refereed Journal, Pp.108–113

This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ. सोनम शर्मा

For publication of Research Paper title

भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में बहु-विषयक शिक्षा: एनईपी 2020 की कार्यान्वयन रणनीतियों का एक विवरणात्मक अन्वेषण

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-04, Issue-04, Month January, Year-2026, Impact Factor (RPRI-4.73)

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor- In-chief

Dr. Neeraj Yadav
Executive-In-Chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://theresearchdialogue.com/

DOI: : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v4i4.14